गृह कर बकायेदारों पर कार्रवाई, कई भवन सील, लाखों की वसूली

लखनऊ। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को नगर निगम लखनऊ द्वारा गृह कर वसूली को लेकर शहर के विभिन्न जोनों में सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में गृह कर जमा न करने वाले भवन स्वामियों के विरुद्ध सीलिंग और कुर्की की प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार, 09 जनवरी 2026 को जोन-1 और जोन-8 में चलाए गए अभियानों में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई भवनों को सील किया और मौके पर ही लाखों रुपये की वसूली भी की।

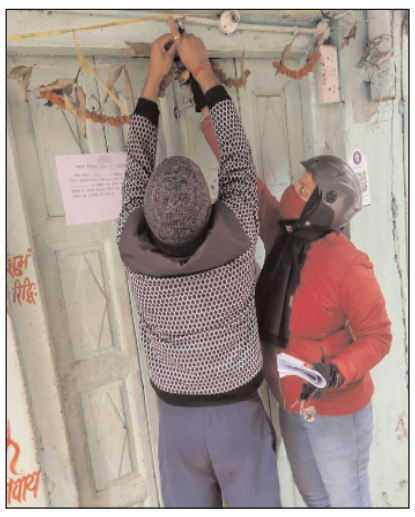

नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार जोन-1 के अंतर्गत जे.सी. बोस वार्ड क्षेत्र में गृह कर बकाया न जमा करने पर भवन संख्या 47/057, विधानसभा मार्ग पर स्थित एक व्यावसायिक भवन को सील किया गया। यह भवन अतुल चरण व अन्य के नाम दर्ज है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं संचालित हैं। इस भवन पर कुल बकाया गृह कर की राशि 16,27,147 रुपये थी। सीलिंग की कार्रवाई के पश्चात भवन स्वामी द्वारा तत्काल 4,00,000 रुपये नगर निगम में जमा किए गए, साथ ही 4,00,000 रुपये का अग्रिम तिथि का चेक भी निगम को प्रदान किया गया। फरीदा इकबाल के नाम दर्ज भवन संख्या 118/088-वी, कैंट रोड को भी गृह कर बकाया 4,29,695 रुपये का भुगतान न किए जाने के कारण सील किया गया।

जोन-2 के अंतर्गत भी बड़े बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। भवन संख्या-243/11, भवन स्वामी श्रीमती प्रीति जायसवाल पर 65,046 रुपये का बकाया पाया गया। सीलिंग की कार्रवाई के दौरान भवन स्वामी द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके निस्तारण के उपरांत 55,045 रुपये की धनराशि नगर निगम कोष में जमा कराई गई। वहीं भवन संख्या-252/05, भवन स्वामी ईश्वर मॉल पर 58,337 रुपये का बकाया होने के कारण सीलिंग की गई, जिसमें आंशिक भुगतान के रूप में 19,000 रुपये प्राप्त हुए।

जोन-8 में गृह कर बकायेदारों के खिलाफ कुर्की एवं सीलिंग का व्यापक अभियान चलाया गया। वार्ड राजा बिजली पासी प्रथम क्षेत्र में कुल पांच भवनों एवं प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। इनमें भवन संख्या 123 -66, और 227 शामिल हैं। इन सभी भवनों पर कुल बकाया गृह कर की राशि लगभग 58 लाख रुपये से अधिक थी।कुर्की की कार्रवाई के दौरान मौके पर ही दो भवनों से कुल 8,40,562 रुपये की वसूली नगर निगम कोष में कराई गई। यह भुगतान भवन संख्या 123 से 3,40,533 रुपये तथा भवन संख्या 66 से 5,00,029 रुपये के रूप में प्राप्त हुआ।

65 जिलों के गौ-आश्रय स्थलों पर मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम लागू, शेष में प्रक्रिया जारी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के गौ-आश्रय स्थलों पर लगातार निगरानी, प्रबंधन और सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य तेज गति से जारी है। प्रदेश के 75 जनपदों के कुल 6718 ग्रामीण गौ-आश्रय स्थलों में से 65 जनपदों के 4366 गौ-आश्रय स्थलों पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है। बाकी जनपदों में भी निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किए जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

साथ ही प्रदेश के हरदोई, आगरा, जालौन सहित 20 जनपदों के विकास भवनों में केंद्रीकृत निगरानी कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं, जिसके माध्यम से आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं पर सतत नजर रखी जा रही है। योगी सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। गौ-आश्रय स्थलों पर गोवंश के लिए शेड, स्वच्छ भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था, खड़ंजा, भूसा भंडार गृह, उपचार कक्ष, प्रकाश और सोलर लाइट जैसी सुविधाओं को सुदृढ़ और व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि गौ-आश्रय स्थलों की बेहतर निगरानी एवं व्यवस्था के समन्वय के लिए राज्य के 20 जनपदों के विकास भवनों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं।

हरदोई, आगरा, जालौन, झांसी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, जौनपुर, अयोध्या, आजमगढ़, पीलीभीत, कौशांबी, शामली, बस्ती, अंबेडकरनगर, बलिया, एटा, अमरोहा, फर्रुखाबाद और चंदौली में ये कंट्रोल रूम कार्यरत हैं। शेष जनपदों में भी चरणबद्ध ढंग से यह व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि निगरानी तंत्र मजबूत होने से गौवंश की देखभाल अधिक व्यवस्थित और जिम्मेदाराना ढंग से हो रही है। किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में तत्काल कार्रवाई संभव हो रही है।

गो-आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के साथ-साथ ठंड से सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्थलों पर हरा चारा, तिरपाल, काउ-कोट, अलाव, औषधियां, उपचार सुविधा और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ठंड अथवा अव्यवस्था के कारण किसी भी गोवंश की मृत्यु न हो।

संक्षिप्त समाचार

भाजपा सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार के सारे दावे झूठे हैं। इस सरकार का जीरो टॉलरेंस का वादा जीरो हो चुका है। मेरठ में माँ पर क़ातिलाना हमला और बेटी को उठाकर ले जाने का मामला बेहद गंभीर है। भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण देते-देते आज जिस स्तर पर पहुँच गयी है, वहाँ से वापस नहीं लौट सकती क्योंकि अपराधी उनके राज़ खोल देंगे। सरकार से कोई उम्मीद ही न बचे, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। भाजपा पूरी तरह नाकाम सरकार है। श्री यादव ने कहा कि महिला अपराध और साइबर क्राइम में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर पहुंच गया है। इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोज 5 महिलाएं हिंसा का शिकार व हर 15 दिन में दुष्कर्म की शर्मनाक घटना हो रही है। पूरे प्रदेश में इसी तरह से हत्या, लूट बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। सरकार झूठे विज्ञापनों से चाहे जितने दावे करे लेकिन वह सच्चाई को छुपा नहीं सकती है। महिला सुरक्षा के झूठे दावे करने वाले मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता 2027 में सत्ता से बाहर कर देगी। श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार और लूट के कारण प्रदेश में तमाम तरह के अपराध पनप रहे हैं। जिसे पहले लोग स्थानीय अपराध समझ रहे थे, जब पहली परत खुली तो वो राज्यव्यापी निकला, फिर एक और परत खुली तो राष्ट्रव्यापी निकला और अब एशिया लेवल का क्राइम निकल रहा है। उत्तर प्रदेश में माफ़िया राज ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि प्रमोशन पा गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का 'महा-माफ़िया राज' है, जो लोगों के घरों में 'बोतल-बंद' होकर पहुँच रहा है और जानलेवा साबित हो रहा है। इस अरबों की काली-कमाई में 'सत्ताधारी की भागीदारी' है, इसीलिए भाजपा राज में मारी-मारी फिर रही जनता अभागी है। भाजपा अंतिम पारी का अंतिम चरण खेल रही है, उसके ओवर अब 'ओवर' हो गये हैं। भाजपा की पूरी टीम मैच ख़त्म होने से पहले ही 'ऑल आउट' हो रही है।

वर्षों बाद एकजुट होकर संघर्ष करेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम को 29 को ज्ञापन कार्यक्रम

लखनऊ । सालों बाद एकजुट हुई आंगनबांडी कार्यकर्ता के चारों संगठन अब एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करेंगें। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कार्यालय महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ में आयोजित बैठक में आंगनबाड़ी के चारों संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है।

बैठक में संयुक्त मोर्चा में श्रीमती नीलम पाण्डेय महामंत्री महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के शामिल होने पर उनका आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बैठक में अन्य संगठनों के शीर्ष पदाधिकारियों ने मोर्चे में उनके शामिल होने पर मोर्चे के और मजबूत एवं संघर्षशील रूप से कार्य करने इरादा जताया। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों की पूर्ति के लिए प्रत्येक जनपद में 29 जनवरी 26 को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भ्रोजा जाएगा। बैठक में मोर्चे के शीर्ष पदाधिकारी श्रीमती गीतांजलि मौर्य, श्रीमती शशिबाला, श्रीमती सुषमा कुरील, श्रीमती नीलम पाण्डेय, श्रीमती रामादेवी, अनूप मिश्रा, मिथलेश चौधरी, हीरावती, श्रीमती माया, कल्पना सिंह, कंचन राय, राजेश शर्मा, ज्योत्सना, अमरेन्द्र सिंह की उपस्थिति में आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा की बैठक में 10 सूत्रीय मांग पर विचार विमर्श किया गया।

बैठक में इस बात पर चिन्ता जताई गई की लगातार पत्रचार और संकेतिक प्रदर्शन के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण नही हो पा रहा है। बैठक में कहा गया कि लगभग पचास वर्षो के कार्यकाल में यह ऐसा मौका है जब अलग अलग आंगनबांडी संगठन एक बैनर तले आ गए है। अब मौका है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए एकजुट होकर संघर्ष किया जाए। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पूर्ण कालिक राज्य कर्मचारी का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार पेंशन और ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष, मुख्य सेविका और सहायिकाओं के पदों पर पदोन्नति सहित महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा की गई।

अवकाश के दिन भी खुलेगें नगर निगम के जोनल कार्यालय

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ ने वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राजस्व संग्रहण को गति देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नगर आयुक्त के आदेशानुसार आगामी शनिवार एवं रविवार, 10 व 11 जनवरी 2026 को नगर निगम के समस्त जोनल कार्यालय एवं कर काउंटर सुबह 10.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक खुले रहेंगे।

वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति में तीन माह से कम का समय शेष रह गया है। इस अवधि में नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करते हुए गृहकर एवं जलकर की वसूली बढ़ाने तथा राजस्व लक्ष्य की पूर्ति के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कर संबंधी कार्य किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।इन दोनों दिनों में नगर निगम के सभी जोनल कार्यालयों में भवनस्वामियों का कर निर्धारण, फीडिंग, संशोधन, आपत्तियों का निस्तारण तथा कर जमा कराने से संबंधित समस्त कार्य किए जाएंगे। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे करदाताओं से संपर्क कर उन्हें बकाया गृहकर व जलकर जमा कराने के लिए प्रेरित करें, जिससे अधिक से अधिक राजस्व संग्रह सुनिश्चित किया जा सके।इसके अतिरिक्त, नगर निगम प्रशासन द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी वार्डों में कैंपों का आयोजन किया जाए और उनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि नागरिकों को अपने ही क्षेत्र में कर निर्धारण एवं कर भुगतान की सुविधा मिल सके। इन कैंपों के माध्यम से कर निर्धारण, कर वसूली और संबंधित समस्याओं के समाधान का कार्य भी किया जाएगा।

आयुष महानिदेशालय को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने का विरोध

लखनऊ। जवाहर भवन-इन्दिरा भवन कर्मचारी महासंघ की एक बैठक महासंघ में सम्पन्न हुई जिसमें कार्यलयों को अन्यत्र किराये के भवनों में शिफ्ट किये जाने का प्रबल विरोध व्यक्त किया गया।महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पाण्डेय एवं कार्यकारी महामंत्री सुशील कुमार 'बच्चा' ने बताया कि जवाहर भवन और इन्दिरा भवन में पर्याप्त स्थान और सुविधाएं होने के बावजूद कई विभागों को किराये के भवनों में स्थानांतरित किया जा चुका है और वर्तमान में भी महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा और आयुष महानिदेशालय को अन्यत्र ले जाने की कार्यवाही चल रही है, जिसके कारण अनावश्यक रूप से वित्तीय भार पड़ेगा।

श्री पाण्डेय एवं श्री बच्चा ने कहा कि एक ओर सरकारी मितव्ययिता की बात कर रही है, दूसरी ओर बिना किसी समुचित कारण के सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार डालकर अन्य स्थानों पर विभागों को शिफ्ट किया जा रहा है। पूर्व में भी पंचायती राज निदेशालय, पेंशन निदेशालय, भूगर्भ विभाग, शारदा सहायक समादेश समेत कई निदेशालय खाली करके अन्यत्र स्थापित हो चुके है, जिनकी कोई आवश्यकता नही थी। उन्होने यह भी कहा कि सचिवालय भवन नजदीक होने के कारण विभागीय बैठकों इत्यादि में आने जाने हेतु भी ये दोनो भवन ज्यादा सुविधाजनक है। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन भी पास होने के कारण आने जाने में जनता को भी सुविधा है। इस प्रकार के प्रयासों से अपने कार्यो को लेकर आने जाने वाले लोगों और अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी अधिक सुविधा जनक है। श्री पाण्डेय व श्री बच्चा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आयुष महानिदेशालय पत्र भेजकर आयुष महानिदेशालय और चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय इन दोनों भवनों में ही बनाए रखने का अनुरोध किया है। बैठक में महामंत्री रामकुमार धानुक आकिल सईद, बब्लू, संजीव त्रिपाठी, उमंग निगम, अजय धानुक, अभिनव त्रिपाठी, दिनेश त्रिपाठी, शफीकुर्रहमान अंसारी, अमन कुमार, दिव्या रानी श्रीवास्तव, सर्वेश मिश्रा, आशीष त्रिपाठी, अंकुर सिन्हा, सूरज मिश्रा, अमित शुक्ला, संजय शुक्ला आदि ने विरोध जताया है।

हड़ताल के पहले जनवरी और फरवरी में सभी प्रान्तों में संयुक्त सभा और सम्मेलन

निजीकरण के विरोध में देशव्यापी समर्थन

लखनऊ । विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने आज यहां जानकारी दी कि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने आज दिल्ली में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में निजीकरण, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 और श्रम संहिता के विरोध में आगामी 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। निजीकरण के विरोध में देशभर के दस बड़े मजदूर संगठनों का समर्थन मिलने से लगातार 408 दिनों से संघर्षरत उप्र के बिजली कर्मियों में भारी उत्साह है।केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच में इंटक, एटक, सीटू, एच एम एस, ए आई यू टी यू सी, सी सी टी यू,सेवा, ए आई सी सी टी यू,एल पी एफ, यू टी यू सी सम्मिलित हैं।

संघर्ष समिति ने बताया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 आम उपभोक्ताओं, किसानों और कर्मचारियों के हितों के विपरीत है। यह बिल संसद में पारित किया जाता है तो इसके बहुत घातक परिणाम होंगे और यह सार्वजनिक क्षेत्र के पॉवर सेक्टर को तबाह कर देगा।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रस्ताव में कहा गया है कि आगामी 16 जनवरी को इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 और बीज बिल के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश भर में ष्प्रतिरोध दिवसष् मनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त बिजली कर्मचारी देश भर में निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने देश भर के मजदूरों का आह्वान किया है कि 16 जनवरी को प्रतिरोध दिवस में सभी ट्रेड यूनियन पूरी तरह सम्मिलित हों और बाद बिजली कर्मियों के साथ सभी प्रान्तों में संयुक्त सभा और सम्मेलन कर व्यापक मोबिलाईजेशन किया जाय।

संघर्ष समिति ने बताया कि अब उप्र के बिजली कर्मियों को देश भर के 25 करोड़ कर्मचारियों और मजदूरों का समर्थन मिलने से उप्र के बिजली कर्मी और उत्साह तथा जोश के साथ निजीकरण के विरोध में संघर्ष तेज करेंगे।पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में आज बिजली कर्मियों में प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

महापौर ने सोमनाथ मंदिर में किए दर्शन

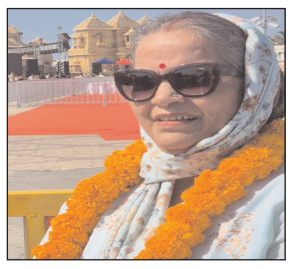

लखनऊ/गुजरात। गुजरात में आयोजित शैक्षिक भ्रमण के दौरान महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल ने शुक्रवार को पवित्र सोमनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन-पूजन किया। इस अवसर पर उनके साथ नगर निगम के माननीय पार्षदगण एवं वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। माननीय महापौर ने मंदिर परिसर में भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर नगर की सुख-समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना की। भ्रमण के दौरान उन्होंने मंदिर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता की जानकारी प्राप्त की। यह शैक्षिक यात्रा सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन और प्रशासनिक अनुभवों के आदान-प्रदान के उद्देश्य से आयोजित की गई।

गुरु तेग बहादुर की वाणी के सार्वभौमिक नैतिक मूल्य आज भी प्रासंगिक

लखनऊ । उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की ओर से गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष और विश्व हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार 09 जनवरी को इन्दिरा भवन में 'राष्ट्रीय चेतना-हिन्द की चादर गुरु तेग बहादुर विषयक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने संदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर की वाणी के सार्वभौमिक नैतिक मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं। इस अवसर पर अकादमी के प्रतिनिधि के रूप में अरविन्द नारायण मिश्र ने संगोष्ठी में उपस्थित वरिष्ठ विद्वानों को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया।

संगोष्ठी में वरिष्ठ पंजाबी विद्वान नरेन्द्र सिंह माँगा ने बताया कि गुरु तेग बहादुर साहिब द्वारा अपनी संपूर्ण वाणी का, हिन्दी में ही उच्चारण किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसे हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता है। दरअसल यह धार्मिक ही नहीं सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु तेग बहादुर की वाणी में सार्वभौमिक नैतिक मूल्य, करुणा, निडरता, धार्मिक सहिष्णुता और बलिदान के संदेश हैं। ये मूल्य किसी विशेष धर्म तक सीमित नहीं हैं और आधुनिक समाज में नैतिक शिक्षा के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। नवयुग कन्या महाविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष मेजर डॉ. मनमीत कौर सोढ़ी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर का बलिदान केवल सिख या हिन्दू समाज के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए था।

कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च त्याग भारतीय संस्कृति की उदार और साहसी परंपरा को दर्शाता है। उनके अनुसार गुरु तेग बहादुर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। वह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्हें 'हिंद दी चादर' अर्थात भारत की ढाल, कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। उनकी जीवनी और शिक्षाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना, छात्रों को भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय से अवगत कराएगा। वरिष्ठ विदुषी डॉ. रश्मि शील के अनुसार गुरु तेग बहादुर साहिब का साहित्यिक सृजन उच्च कोटि का है।

गुरु साहिब की वाणी में पद और दोहे शामिल हैं। उन्हें हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल करने से छात्र हिंदी-ब्रज भाषा के समृद्ध भक्ति साहित्य से परिचित होंगे, क्योंकि उनकी सभी रचनाएं हिंदी की उपबोली ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग की प्रोफेसर, डॉ. अलका पाण्डेय ने कहा कि गुरु तेग बहादुर के त्याग से प्रेरणा लेकर सशक्त और जागरूक राष्ट्र का निर्माण संभव है। कार्यक्रम में मीना सिंह, महेन्द्र प्रताप वर्मा, रवि यादव, अंजू सिंह सहित पंजाबी समाज के गणमान्य जन उपस्थित रहे।

उपभोक्ता परिषद देशव्यापी मंच बनाकर निजीकरण के खिलाफ खोलेगा मोर्चा

लखनऊ। उपभोक्ता परिषद ने निजीकरण के खिलाफ एक देश व्यापी मंच बनाकर आरपार के आन्दोलन का ऐलान किया है। उपभोक्ता की तरफ से कहा गया है कि देश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की विश्वसनीयता को लेकर उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति है ज्यादातर उपभोक्ताओं को अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर भरोसा नहीं है इसके बावजूद भी चेक मीटर की मिलन रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं जारी की गई।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पूरे देश में निजीकरण की प्रक्रिया के चलते बिजली कंपनियां अक्सर विधिक और वित्तीय संकट में फंस जाती हैं। इसके बावजूद बड़े निजी घराने सरकारी बिजली कंपनियों को कम लागत में खरीदने और बड़े लाभ कमाने की योजना में लगे हुए हैं। पूरे देश में उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य रूप से लगाने की योजना देश के उद्योगपतियों की ही है क्योंकि उन्हें पता है कि निजीकरण होने के बाद उनका सबसे ज्यादा लाभ होगा उपभोक्ता परिषद देश के सभी उपभोक्ता संगठनों को एक मंच पर लाकर आर पार की लड़ाई लड़ेगा।

सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के बड़े निजी घराने बैंकों से लोन लेकर अपनी योजना बनाकर सरकारी बिजली कंपनियों को खरीदने के लिए उत्सुक है यह देश का दुर्भाग्य है की सरकारी पैसे से ही सरकारी कंपनी को खरीदने के लिए परेशान है उपभोक्ता परिषद सभी निजी घराने जो उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं उनकी बैलेंस शीट को एक बार नहीं बहुत बार पढ़ चुका है उनकी हैसियत नहीं है कि वह प्रदेश के दो जनपद को भी खरीद सके।

अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि पूरे देश में लगभग तीन लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च करके बिजली कंपनियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया है, वहीं उत्तर प्रदेश में अरडीएसएस योजना लगभग 44,000 करोड़ रुपये की राशि स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना में खर्च की जा रही है। उनका कहना है कि यह प्रयास प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को निजी हाथों में सीमित करने जैसा है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय विद्युत अधिनियम 2003 के अनुच्छेद 47(5) के तहत उपभोक्ताओं को पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों विकल्प उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर जबरदस्ती प्रीपेड मोड में बदल दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 लाख से अधिक कागजों में चेक मीटर स्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन उनकी वास्तविक कार्यक्षमता और मिलान रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है।उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि पूरे देश के सभी उपभोक्ता संगठनों को एक मंच पर लाकर निजीकरण के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और कोई भी उद्योगपति अपने लाभ के लिए उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन सफल नहीं होने देगा।

MGIRI
MAHATMA GANDHI INSTITUTE FOR RURAL INDUSTRIALISATION
(A National Institute under Ministry of MSME, Govt. of India)

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी), वर्धा - 442001
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)
फोन 07152 253512

महात्मा गांधी ग्रामीण **औद्योगिकीकरण** संस्थान (एमगिरी), जो की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थान, वर्धा, महाराष्ट्र में स्थित है ; ग्रुप 'ए' के तीन पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

पद का नाम	संख्या	भर्ती विधि	वेतन (7वें वेतन आयोग के अनुसार)
उप निदेशक	01	प्रतिनियुक्ति द्वारा	वेतन बैंड 4: रु. 37400-67000/-, वेतन स्तर 13
प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी	01	सीधी भर्ती द्वारा	वेतन बैंड 3: रु. 15600-39100/-, वेतन स्तर 12
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	01	सीधी भर्ती द्वारा	वेतन बैंड 3: रु. 15600-39100/-, वेतन स्तर 11

विस्तृत जानकारी के लिए 10/01/2026 को प्रकाशित रोजगार समाचार और एमगिरी वेबसाइट देखें। उपरोक्त पद के लिए आवेदन पत्र और अन्य विवरण कार्यालय की वेबसाइट www.mgiri.org से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

नोट: उपरोक्त विज्ञापन में यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल एमगिरी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

CBC 25134/12/0006/2526

प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी, एमगिरी

पूर्वोत्तर रेलवे

निविदा सूचना संख्या LS-GD-AMC-Medha-SIV-2x130

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजीनियर / टी.आर.एस. / पूर्वोत्तर रेलवे, लोको शेड गोण्डा द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु खुली ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है। **निविदा सूचना संख्या एवं कार्य का नाम, निविदा सूचना संख्याः– LS-GD-AMC-Medha-SIV-2x130,** "गोंडा लोको शेड में स्थित इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में लगे मेधा कंपनी के एसआईवी यूनिट (2 x 130 केवीए) का 3 साल के लिए एएमसी" **अनुमानित लागत (रू मे):**– 3186008.50, **निविदा की अवधिः**– 36 माह, **अग्रिम धन राशि (रू मे):**– 63700.00, • ऑफर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय 29.01.2026, 12:00 बजे।, • इस ई–निविदा से संम्बंधित विस्तृत जानकारी, न्यूनतम अर्हताये तथा नियम एवं शर्तें, रेलवे की वेबसाईट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। • निविदाकार, ई–निविदा प्रपत्र को अपलोड करने से पूर्व इस ई–निविदा से संम्बंधित शुद्धि पत्र (यदि कोई हो) को बेबसाईट पर संज्ञान में लेना सुनिश्चित करे। **नोटः**– 1. इस निविदा के विरुद्ध मैनुअल ऑफर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे प्राप्त मैनुअल ऑफर को उपेक्षित कर दिया जाएगा। 2. विस्तृत विवरण व निविदा जमा करने हेतु, कृपया भारतीय रेलवे कि वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** को देखें।

समंविइं / टीआरएस, लोको शेड
मुजाधि / विद्युत–246 गोण्डा

ट्रेनों में बीड़ी / सिगरेट न पियें